करेंट अफेयर्स 8 अक्टूबर 2022

वैधानिक तरलता अनुपात -परिभाषा

वैधानिक तरलता अनुपात या एसएलआर जमा का न्यूनतम प्रतिशत है जिसे एक वाणिज्यिक बैंक को तरल नकदी, सोना या अन्य प्रतिभूतियों के रूप में बनाए रखना होता है। यह मूल रूप से आरक्षित आवश्यकता है जो बैंकों से ग्राहकों को ऋण देने से पहले रखने की अपेक्षा की जाती है। एसएलआर आरबीआई द्वारा तय किया जाता है और यह भारत में ऋण वृद्धि पर नियंत्रण का एक रूप है।

सरकार मुद्रास्फीति और ईंधन वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए एसएलआर का उपयोग करती है। एसएलआर बढ़ने से अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति पर नियंत्रण होगा जबकि वैधानिक तरलता दर घटने से अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी। एसएलआर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 (2ए) द्वारा निर्धारित किया गया था।

एसएलआर क्यों तय है?

• बैंक ऋण के विस्तार की जाँच करना।

• वाणिज्यिक बैंकों की शोधन क्षमता सुनिश्चित करना।

• बैंकों को बांड जैसी सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए बाध्य करना।

• वृद्धि और मांग को बढ़ावा देने के लिए; यह एसएलआर कम करके किया जाता है ताकि वाणिज्यिक बैंकों के पास अधिक तरलता हो।

यदि कोई बैंक निर्धारित एसएलआर बनाए रखने में विफल रहता है, तो वह भारतीय रिजर्व बैंक को दंड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। डिफॉल्टर बैंक को उस विशेष दिन के लिए कम राशि पर बैंक दर से 3% अधिक जुर्माना देना पड़ता है।

एसएलआर न्यूनतम दर तय करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिस पर बैंक अपने ग्राहकों को पैसा उधार दे सकता है। इस न्यूनतम राशि को आधार दर कहा जाता है। यह भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य पब्लिक डीलिंग बैंकों के बीच पारदर्शिता बनाने में मदद करता है।

भारतीय रिजर्व बैंक वह निकाय है जो एसएलआर निर्धारित करता है। भारतीय रिजर्व बैंक बैंक क्रेडिट को नियंत्रित करने के लिए मुद्रास्फीति के समय एसएलआर बढ़ाता है। मंदी के समय आरबीआई बैंक क्रेडिट बढ़ाने के लिए एसएलआर घटाता है।

नकद आरक्षित अनुपात क्या है?

सीआरआर एक आवश्यक मौद्रिक नीति उपकरण है जिसका उपयोग अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, उस देश के सेंट्रल बैंक द्वारा लगभग हर देश में लागू एक विनियमन।

सीआरआर दर नकद जमा का न्यूनतम प्रतिशत है (जैसा कि आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट किया गया है) जिसे प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक द्वारा सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई की आवश्यकता के अनुसार बनाए रखा जाना चाहिए।

नकद आरक्षित अनुपात दर की गणना प्रत्येक बैंक की शुद्ध मांग और समय देनदारियों के प्रतिशत के रूप में की जाती है। कुल बचत खाते, चालू खाते और सावधि जमा शेष के साथ शुद्ध मांग और समय देयता तक पहुंच जाती है।

सीआरआर . पर कोविड का प्रभाव

कोविड -19 के कारण हुए व्यवधान के कारण, 26 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले एक वर्ष के लिए सभी बैंकों के सीआरआर को 100 आधार अंकों से घटाकर 3.0 प्रतिशत कर दिया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने धीरे-धीरे बहाल करने का निर्णय लिया है। नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) दो चरणों में गैर-विघटनकारी तरीके से।

हालांकि सीआरआर दर की अनुमेय सीमा 3 से 15% के बीच है, भारत का वर्तमान सीआरआर 3% है। यानी बैंकों को अपनी जमा राशि में 100 रुपये की बढ़ोतरी होने पर 3 रुपये आरबीआई के पास रखने होंगे। उच्च सीआरआर का मतलब है कि बैंकों के पास उधार देने या निवेश करने के लिए कम राशि उपलब्ध है यानी कम तरलता होगी और इसके विपरीत।

यहां तक कि जब आरबीआई ने सीआरआर को 4 प्रतिशत तक बहाल करने की घोषणा की, तो केंद्रीय बैंक ने बैंकों को उनकी तरलता आवश्यकताओं पर आराम प्रदान करने के लिए सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) में छूट को छह और महीनों के लिए 30 सितंबर, 2021 तक बढ़ा दिया।

सीआरआर . की परिभाषा

नकद आरक्षित अनुपात ग्राहक की कुल जमा राशि की एक विशेष न्यूनतम राशि है जिसे वाणिज्यिक बैंक द्वारा आरक्षित के रूप में या तो नकद या आरबीआई के पास जमा के रूप में बनाए रखने की आवश्यकता होती है। सीआरआर दर सेंट्रल बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार तय की जाएगी।

व्याख्या – नकद आरक्षित अनुपात के रूप में निर्दिष्ट राशि आरबीआई के पास नकद या नकद समकक्ष में रखी जाती है या आरक्षित होती है। सीआरआर का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंकों के पास अपने जमाकर्ताओं की भुगतान मांगों को पूरा करने के लिए नकदी की कमी न हो।

सीआरआर के लाभ

सीआरआर समग्र तरलता का प्रबंधन करने के लिए अर्थव्यवस्था में धन परिसंचरण को फैलाने में मदद करता है। वित्तीय बाजार में मुद्रा आपूर्ति के अनुसार सीआरआर दर तय की जाती है। जब मौद्रिक आपूर्ति में वृद्धि होती है, तो आरबीआई अतिरिक्त धनराशि को हटाने के लिए तुरंत सीआरआर बढ़ा देता है। इसी तरह, तरलता की कमी या अर्थव्यवस्था में मौद्रिक आपूर्ति में कमी के मामले में, आरबीआई बाजार में अधिक पैसा देने के लिए सीआरआर दर में कमी करेगा। आइए नकद आरक्षित अनुपात के अन्य लाभों पर एक नज़र डालें।

- सीआरआर वाणिज्यिक बैंकों को सॉल्वेंसी की स्थिति बनाने और बनाए रखने में मदद करता है।
- यह सुनिश्चित करता है कि सभी वाणिज्यिक बैंकों में चलनिधि प्रणाली सुसंगत और अच्छी तरह से बनी रहे।
- आरबीआई को सीआरआर दर के माध्यम से बैंकों द्वारा बनाए गए क्रेडिट को नियंत्रित और समन्वयित करना पड़ता है जो अर्थव्यवस्था में नकदी और ऋण की सुचारू आपूर्ति में मदद करता है।
- जब आरबीआई द्वारा सीआरआर दर कम की जाती है, तो वाणिज्यिक बैंक उधारकर्ताओं को अधिक अग्रिम की पेशकश कर सकते हैं जो बदले में जनता के लिए नकदी के प्रवाह को बढ़ाता है।
- सीआरआर बाजार की ब्याज दरों में भारी गिरावट आने पर चलनिधि को अवशोषित करके घटती दर में सुधार करने में मदद करता है।
- बाजार स्थिरीकरण योजना बांड जैसे अन्य मौद्रिक साधनों की तुलना में नकद आरक्षित अनुपात कार्यान्वयन अधिक प्रभावी है। मुख्य रूप से क्योंकि एमएसएस बांड देश में तरलता प्रणाली को नियंत्रित करने में काफी समय लेते हैं।
- रुपये के अधिशेष की स्थिति के दौरान, सीआरआर वित्तीय माहौल को आसान बनाने में रचनात्मक भूमिका निभाता है।

नकद आरक्षित अनुपात का महत्व

बैंकों द्वारा बनाए रखा नकद आरक्षित अनुपात बैंकों के साथ-साथ जमाकर्ताओं दोनों के लिए महत्वपूर्ण है।

जमाकर्ताओं के मामले में, जब बैंक ईमानदारी से आवश्यक सीआरआर दर बनाए रखते हैं, तो जमाकर्ताओं को अपनी जमा राशि के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनके पैसे का एक हिस्सा आरबीआई के पास रखे रिजर्व के रूप में सुरक्षित है।

बैंकों के लिए सीआरआर का महत्व निम्नानुसार है:

बैंक ग्राहकों को मुख्य रूप से उधार देने के लिए जमा खोलने की अनुमति देते हैं। बैंक उधारकर्ताओं को अधिक से अधिक धनराशि उधार देना पसंद करते हैं और अन्य उद्देश्यों के लिए बहुत कम धन अपने पास रखते हैं। इसलिए सीआरआर रेट कम होने पर बैंक इसे पसंद करते हैं।

बैंकों द्वारा अधिकतम उधार देने से उन्हें उच्च लाभ प्राप्त करने में मदद मिलती है। हालांकि, बैंकों के पास निकासी की अचानक मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन होता है जब वे अपने पैसे का एक बड़ा हिस्सा उधार देने के लिए उपयोग करते हैं।

यहीं से सीआरआर तस्वीर में आता है। ऐसी स्थितियों से बचने के लिए जहां बैंक धन की कमी के कारण पुनर्भुगतान को पूरा नहीं कर सकता है, आरबीआई द्वारा नकद आरक्षित अनुपात दर तय की जाती है।

उच्च मुद्रास्फीति के समय में नकद आरक्षित अनुपात कैसे मदद करता है?

उच्च मुद्रास्फीति के समय, सरकार को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त धन उपलब्ध न हो।

• उस हद तक, आरबीआई नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि करता है और बैंकों के पास उपलब्ध धन की मात्रा कम हो जाती है। यह अर्थव्यवस्था में धन के अतिरिक्त प्रवाह को रोकता है।

सीआरआर . के प्रभाव

सबसे पहले, सीआरआर का मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि जमा के खिलाफ धन का एक छोटा हिस्सा हमेशा उपलब्ध हो। दूसरा, देश में आरबीआई नियंत्रण दरों और समग्र तरलता को सक्षम करना है।

अब, बैंक कम होने पर सीआरआर पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें आरक्षित निधि पर कोई ब्याज अर्जित किए बिना आरबीआई के साथ धन के निर्दिष्ट अनुपात को बनाए रखने की आवश्यकता होती है, जिसका अर्थ है कि पैसा मुफ्त में रखा जाता है।

बढ़ी हुई सीआरआर दर का मतलब है कि बैंकों के पास फंड के मामले में कम उधार देने की क्षमता है। नतीजतन, बैंक अधिक जमा खाते खोलना चाहेंगे। साथ ही, बैंक ब्याज दर में वृद्धि करेंगे जो उधारकर्ताओं को ऋण के लिए आवेदन करने से हतोत्साहित करेगा क्योंकि उच्च ब्याज दरें उच्च ऋण व्यय का संकेत देती हैं।

यदि किसी जमाकर्ता ने बैंक शेयरों में निवेश किया है, तो बढ़ी हुई सीआरआर दर इंगित करती है कि उनके बैंक का मार्जिन कम होगा।

इसी तरह, जब सीआरआर दर कम होती है, तो बैंकों के पास अन्य व्यवसायों में निवेश करने के लिए अधिक पैसा होता है, इससे ऋण पर लगने वाली ब्याज दरें कम हो जाती हैं।

साथ ही, कम नकद आरक्षित अनुपात का अर्थ है कि बैंकिंग प्रणाली की मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगी। बढ़ी हुई मुद्रा आपूर्ति का अर्थ है उच्च मुद्रास्फीति।

नकद आरक्षित अनुपात Gist में

नकद आरक्षित अनुपात या सीआरआर अधिकांश देशों में केंद्रीय बैंकों द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक विनियमन है जिसके द्वारा यह ग्राहक जमा और मुद्रा का न्यूनतम अंश निर्धारित करता है जिसे प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक को अपने पास भंडार के रूप में रखने की आवश्यकता होती है। आवश्यक भंडार आम तौर पर केंद्रीय बैंक के पास जमा के रूप में या बैंकों की तिजोरियों में भौतिक रूप से संग्रहीत नकदी के रूप में होते हैं। सीआरआर को रिजर्व रिक्वायरमेंट भी कहा जाता है।

सीआरआर का उपयोग अक्सर केंद्रीय बैंक द्वारा देश के ब्याज और उधार दरों को प्रभावित करने के लिए एक मौद्रिक नीति उपकरण के रूप में किया जाता है, जिससे बैंकों को ऋण देने के लिए उपलब्ध धन में परिवर्तन होता है। जब सरकार को सिस्टम में धन पंप करने की आवश्यकता होती है, तो यह सीआरआर दर को कम करती है, जो बदले में, बैंकों को बड़ी संख्या में व्यवसायों और उद्योगों को निवेश उद्देश्यों के लिए ऋण प्रदान करने में मदद करती है। कम सीआरआर अर्थव्यवस्था की विकास दर को भी बढ़ावा देता है।

पश्चिम में, केंद्रीय बैंक शायद ही कभी सीआरआर में बदलाव करते हैं क्योंकि इससे कम अतिरिक्त भंडार वाले बैंकों के लिए तत्काल तरलता की समस्या पैदा होगी। वहां, वे आम तौर पर मौद्रिक नीति को नियंत्रित करने के लिए सरकारी बॉन्ड को बेचने और खरीदने जैसे खुले बाजार के संचालन का उपयोग करना पसंद करते हैं। चीन में, केंद्रीय बैंक (पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना) मुद्रास्फीति से लड़ने के लिए सीआरआर का उपयोग एक उपकरण के रूप में करता है। इसने 2007 में आरक्षित आवश्यकता को 10 गुना और 2010 की शुरुआत से 11 गुना बढ़ा दिया था।

चीता परिचय परियोजना निगरानी: केंद्र ने 9 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया

चीता परिचय परियोजना निगरानी: केंद्र ने मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान और अन्य उपयुक्त निर्दिष्ट स्थानों में चीतों की शुरूआत की निगरानी के लिए एक टास्क फोर्स की स्थापना की है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) चीता टास्क फोर्स के संचालन का समर्थन करेगा और सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगा। मध्य प्रदेश के वन और पर्यटन के प्रधान सचिव, साथ ही नई दिल्ली में एनटीसीए के महानिरीक्षक डॉ अमित मलिक, टास्क फोर्स के नौ सदस्यों में शामिल होंगे।